

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 323 राँची ,मंगलवार

24 आषाढ़ 1936 (श॰)

15 जुलाई, 2014 (ई॰)

नगर विकास विभाग।

अधिसूचना 4 मार्च, 2014

संख्या-1/स्था0/मु0स्था0/न0 वि0/131/2011-985-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के अध्याय-39 की सहपठित धारायें 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 एवं 454 में नगर निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी एवं उनके समकक्ष पदाधिकारियों को भवन निर्माण की स्वीकृति एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कृत्यों के संबंध में शिक्तयाँ प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त धाराओं के संदर्भ में निकाय के पदाधिकारियों द्वारा की गयी कार्रवाई (Action) के विरूद्ध उद्भूत अपीलीय मामलों पर सुनवाई एवं विनिश्चय (Hearing & Decision) करने के लिए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-442 में निहित झारखण्ड नगरपालिका

भवन न्यायाधिकरण की अपीलीय शक्तियाँ राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकारण को अधिकृत करते हैं।

- 2. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अन्तर्गत संचालित अपीलीय प्राधिकार का क्षेत्राधिकार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से झारखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों पर होगा।
- 3. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-2001 (अंगीकृत) की धारा-89 (5), 90 एवं 91में अंकित प्रावधानों के अध्ययधीन राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्य भी पूर्ववत् करते रहेंगे।
- 4. अपीलीय न्यायधिकरण को सिविल प्रोसिड्योर कोड 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- 5. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अध्याय-39 में अंकित अपील से संबंधित मामले परिसीमा अधिनियम, 1963 के भाग-॥ एवं भाग-॥ के उपबंध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-442 के अधीन दायर प्रत्येक अपील पर भी लागू होगें।
- 6. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में गठित अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील हेतु लिम्बत मामला एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अध्याय-39 में किये गये उपबंध से संबंधित कोई भी मामला किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में नहीं लाया जायेगा,

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
